

(b) whether it is a fact that Government have received any representation from the Institute of Chartered Accountants of India in the matter; if so, what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA) (a) No, Sir. The case is still under the investigation by the Police.

(b) Yes, Sir. The case is still under the investigation and only after it has been completed, the real circumstances concerning this incident would be known. BCCL is fully co-operating with the Auditors.

#### Power Projects of Andhra Pradesh

2429. SHRI G. SWAMY NAIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the number and names of power projects reports sent by the Government of Andhra Pradesh which are still pending with the Central Government for approval; and

(b) by when these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The following projects have been received for approval:

(1) Jalaput Dam. . . . .	(18 MW)
P.H.	
(2) Kakatiya Canal . . . . .	(15 MW)
Power House	
(3) Kakatiya Feeder Canal	
Micro Hydle . . . . .	(2 MW)
(4) Penna Ahobilam . . . . .	(20 MW)
(5) Pochampad H.E.P. . . . .	(27 MW)
(6) Nagar Junasagar L.B.C. . . . .	(60 MW)
(7) Vijayawada Ext. T.P.S. . . . .	(420 MW)

The first three projects are under appraisal for techno-economic clearance in the Central Electricity Authority. Penna Ahobilam is

awaiting clearance of Department of Environment from environmental angle. The other three projects are under process in the Planning Commission.

(b) The various issues involved under the proposals have to be resolved during the appraisal of the Project. No time limit is laid down for the clearance of the project proposals. Central Electricity Authority, as a statutory body, is obliged to clear only such projects which represent the best technical and economic alternatives to meet the system requirements.

#### उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

2430. श्री कलराज मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1982 के दैनिक "जागरण" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में बिजली संकट की संभावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार 1982-83 के वर्ष के दौरान राज्य में बिजली की मांग और पूर्ति में अन्तर को देखते हुए क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या उक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप समुचित मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में इस वर्ष विद्युत् की स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छी है। तथापि, उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्पादन लगभग 40 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इसकी तुलना में आवश्यकता लगभग 44 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इस प्रकार राज्य में कमी लगभग 4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन (9 प्रतिशत) है पूर्वानुमान के

अनुसार आने वाले महीनों में राज्य में ऊर्जा की मामूली कमी रहेगी। राज्य में विभिन्न ताप विद्युत् केन्द्रों को उचित गुणवत्ता वाले तथा पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार सभी उपाय कर रही है। राज्य में विद्युत् की स्थिति में उस समय सुधार हो जायेगा जब ओबरा में हाल ही में चालू की गई 210 मेगावाट की यूनिट स्थिर हो जायेगी। सिगरौली में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से भी राज्य को अपना भाग मिल रहा है।

### उत्तर प्रदेश की तापीय बिजली परियोजनाएं

2431. श्री कलराज मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित चार तापीय बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपनी मंजूरी न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है ; और

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन तथा भौगोलिक जटिलता को देखते हुये, अपने निर्णय पर पुनः विचार करेंगी?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान चालू करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से

निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये थे :—

### मेगावाट

(1) अनपारा "ख"	2 × 500
(2) अनपारा "ग"	3 × 500
(3) दोहरीघाट	2 × 210
(4) परीछा विस्तार	2 × 210
(5) रोसा	2 × 210
(6) जवाहरपुर (एटा)	3 × 210
(7) ऊंचाहार	2 × 210
(8) ऊंचाहार विस्तार	2 × 210
(9) नरोरा	3 × 210

उपयुक्त स्कीमों में से, ऊंचाहार (2 × 210 मेगावाट) और अनपारा "ख" (2 × 500 मेगावाट) तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी गई हैं और निवेश हेतु स्वीकृत कर दी गई हैं। जहां तक रोसा स्कीम (2 × 210 मेगावाट) का संबंध है, यह तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है। जहां तक नरोरा स्कीम (3 × 210 मेगावाट) का संबंध है, यह उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस लौटा दी गई थी क्योंकि परमाणु विद्युत् केन्द्र के पास, जिसे स्थापित किया जा रहा है, विद्युत् केन्द्र स्थापित करना वांछनीय नहीं समझा गया था। शेष स्कीमों में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस लौटा दी गई हैं क्योंकि परियोजना प्रस्तावों में परिकल्पित समय सीमा में उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

ताप विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है जैसे क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकता,